



VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS

MN 07 OCT 2017

SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 876)

Name of Candidate	S. CHANDRA	Registration Number	41040
Medium Eng./Hindi	Hindi	Date	07/10/2017
Center	MN		

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. While India has taken a number of steps in order to substantially improve its ranking in the World Bank's 'Ease of Doing Business' Index, it needs to take further action in this regard. Elaborate. Also analyse the utility of these rankings vis-a-vis India's objective of facilitating a sound entrepreneurial environment.

जहाँ, भारत ने विश्व बैंक के 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने की सुगमता) सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सार्थक सुधार करने हेतु कई कदम उठाए हैं, वहीं भारत को इस संबंध में आगे और अधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए। साथ ही सुदृढ़ उद्यमिता वातावरण प्रदान करने के भारत के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में ऐसी रैंकिंग की उपयोगिता का भी विश्लेषण कीजिए।

वर्तमान में किसी भी अर्थव्यवस्था की तीव्र एवं सतत संवृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है अतः निजी निवेश के बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। निजी निवेश का संबंध स्थानीय एवं वैश्विक स्तरों से प्राप्त निवेश से है।

निवेश बढ़ाने के लिए किये गए सुधारों के आधार पर विश्व बैंक 'इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सूचकांक जारी करता है, जिसके आधार पर वैश्विक निवेशक

अपना गंतव्य निर्धारित करते हैं।

भारत में ईए ऑफ ड्रिंग बिलनेस सूचकांक को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं -

- (i) सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा के माध्यम से पंजीकरण में सहजता।
- (ii) श्रम-सुविधा पोर्टल के तहत प्रतिस्पर्धी एवं पेशगीव मूल्य पर श्रम आपूर्ति
- (iii) भूमि उपचिह्नण के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक माहौल।
- (iv) नीति आयोग का ईए ऑफ ड्रिंग बिलनेस रिपोर्ट के आन्वय पर राज्य-स्तरीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।
- (v) विद्युत प्रदाता में सुगमता के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाना एवं ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा संचरण करना।

भारत में विभिन्न कर्मों के बावजूद विश्व बैंक के ईए ऑफ ड्रिंग

विशेष सूचकांक में 130 वीं स्थान बना हुआ है जो भारत में निवेश के लिए उपलब्ध संपत्ति के पूर्ण दोहन में अवरोध का कार्य करती है। अतः निम्नांकित कदमों की आवश्यकता है।

- (i) श्रम. मानकों का एकीकरण करना एवं वैश्विक मानकों के अनुसार स्वरूप उठान करना।
- (ii) उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा का कवरेज राष्ट्रीय तक रिस्ता करना।
- (iii) स्की हुई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना तथा ग्रीनफील्ड निवेश प्रोत्साहित करना।

वर्तमान में भारतीय गैर वित्तीय उद्योगों से वैश्विक वित्तीय परिवेश से कुछ दूरी है अतः वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए वैश्विक सूचकांक के अनुसार ~~कदम~~ ढांचे का निर्माण आवश्यक है।

2. In wake of the agrarian crisis that the country is witnessing, discuss the need for adopting an income-centric approach in preference to a production-centric one as the basis of agricultural policy. In this context, also highlight the steps that should be taken to achieve the goal of doubling the income of farmers by 2021-22 and the challenges that exist.

देश द्वारा सामना किए जा रहे कृषि संकट के आलोक में, कृषि नीति के आधार के रूप में उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर आय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में, 2021-22 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उनके साथ-साथ विद्यमान चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है।
यहाँ कृषि ५४.९ प्रतिशत संयोजन को
निधोजित करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप
से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की माँग
को प्रभावित करती है। अतः कृषि क्षेत्र की
मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है।

भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं
में कृषि उत्पादन बढ़ाने को उद्देश्य बनाया
गया जिसकी परिणति के रूप में कृषि-
उत्पादन तो बढ़ा किन्तु क्षेत्रीय एवं
व्यक्तिगत विषमता युक्त इस वृद्धि के
कारण कुछ ही किसान समूह लाभान्वित
हुए तथा विषमता में वृद्धि हुई।

द्वितीय क्रांति में सिर्फ अंगाल फासलों पर चल दिए जाने के कारण फासल - उत्पन्न में बदलाव हुआ तथा कृषि-प्रलवायु दशाओं के उत्कृष्ट फासल उत्पन्न में कृषि - इन्फुट लागत में वृद्धि हुई अतः किसानों की शुद्ध आय या कृषि दक्षता में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई ।

आय आचारेण दृष्टिकोण से कृषि आगत मूल्य में कमी एवं उत्पाद मूल्य में वृद्धि करा किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने पर चल दिया जाता है ।

किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए निम्नांकित कदमों की आवश्यकता है -

- (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSRP) नीति को मार्किट बनावट बलहण, तिलहण, सोरे-अनाज के उत्पादन को साझाकारी बनाना होगा ताकि कृषि-प्रलवायु उद्योग के अनुमान

उत्पादन हो और कृषि आगत मूल्य में
कमी आई।

- (ii) कृषि अवसंरचना (सिंचाई, भंडारण,
क्रेडिट विरी, बाजार मण्डी) पर सार्वजनिक
निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।
- (iii) सरकारी नीतियों जैसे प्रधानमंत्री कृषि-
सिंचाई योजना, भूदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल
बीमा योजना का बेहतर कार्यान्वयन
कर इनका सार्वभौमिकरण करना।
- (iv) कृषि मृत्तु सुविधाओं को पहनीय कृषि
मूल्य पर एवं समर्थक तरीके से
उपलब्ध करना।

— पुनर्निर्माण —

- राज्या सूची के विषय होने के कारण
राज्यों का आवश्यकतात्मक श्रेय।
- अशिक्षा, गैर-लाभकारी बिजली एवं अन्य
सामाजिक कठिनाईयों का प्रभाव।

3. It is argued that India's fiscal centre of gravity has rapidly shifted from the Centre to the States. Analyse the statement in context of the debate on fiscal discipline. Also, enumerate the key recommendations of the N.K. Singh panel on Fiscal Responsibility and Budget Management Act.

यह तर्क दिया जाता है कि भारत का राजकोषीय गुरुत्वाकर्षण का केंद्र तेजी से केन्द्र से राज्यों की ओर स्थानांतरित हुआ है। राजकोषीय अनुशासन पर वाद-विवाद के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पर एन. के. सिंह पैनल की प्रमुख अनुशंसाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

भारत में संघवादी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है एवं वित्तीय शक्तियों को भी संघ एवं इतकी इकाइयों में प्रिकाजित किया गया है।

विघ्नावादी इकाइयों के कारण केंद्रीय नियोजन प्रणाली अकार्यवाहक होती है। लगी सौंवि राज्यों के बीच विषमता उत्पन्न करने लगी है तथा राज्यों की विशेष क्षमताओं का दोहन नहीं हो पा रहा है।

अतः राजकोषीय विकेंद्रता का राज्यों की विकेंद्रिकता ~~का~~ क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को सम्मान / महत्व दिया गया। इसी क्रम में राजकोषीय विकेंद्रता अपनाया गया जैसे -

~~एवं संघीय संस्थाओं को~~

- 88 वीं संविधान संशोधन
- 80 वीं संविधान संशोधन
- 14 वीं वित्त आयोग के अनुसार विभाज्य
पूल का राज्यों का हिस्सा 32% से
बढ़कर 42%।
- GST - पत्रिका में राज्यों की इन्वेन्ट्री-रिहाई
मांगी जाती है।

पारंपरिक संघवाद को बढ़ावा
देना तथा विकेंद्रीकृत नियोजन के उद्देश्यों
की पूर्ति के लिए राजकोषीय विकेंद्रण का
होना आवश्यक है। किंतु राज्यों में
शासन गुणवत्ता कमजोर हो, अध्याया एवं
अभ्यर्थित होने के कारण, राजनीतिक
तुष्टिकरण के कारण राजकोषीय
अनुशासन कमजोर हो सकता है। 14 वें
वित्त आयोग द्वारा राज्य के राजकोषीय
अनुशासन की विभाजन योग्य पूल के

वैद्यार्थी के मानकों से हटाने से यह ~~को~~ समस्या और अधिक बढ़ सकती है। अतः राज्यों के राजकोषीय अभाव को मजबूत बनाने के लिए प्रयास आवश्यक है। इसके लिए निम्नांकित कदम/उपाय आवश्यक हैं:-

- (i) राजकोषीय अभाव को वित्त आयोग के विभाजन मानकी में शामिल करना चाहिए।
- (ii) सभी राज्यों की लक्ष्यगति से मॉडल गिनत बनाने की आवश्यकता है ताकि आधारभूत तत्वों का समावेशन उसके राज्य की नीतियों में हो।
- (iii) अभाव को दृष्टिकोण पुनर्गठन के लिए ई-गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए।

NK सिंह पैगल -

- (i) ~~किसी~~ राजकोषीय सुदृढ़ता का लक्ष्य एक सिद्ध नहीं होकर एक पराव (Range) होना चाहिए।
- (ii) राज्यों के महशुआन पर चल।

4. Strategic sale of state-run firms is a prudent step to deal with the challenges being faced by the public sector enterprises in India. Comment. Also enumerate other measures that can be taken in light of NITI Aayog's suggestions in this regard.

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य-संचालित उद्यमों की रणनीतिक बिक्री एक विवेकपूर्ण कदम है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही इस संबंध में नीति आयोग के सुझावों के प्रकाश में उठाए जा सकने वाले अन्य उपायों को भी सूचीबद्ध कीजिए।

भारत में खंडित विकास (growth-poles) की स्थापना कर विकासमक अव्योक्ति निर्यात (downward filtration) की संकल्पना को स्थापित करते तथा प्रादेशिक विषमता की समाप्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) की स्थापना की गई।

संसाधन आवश्यकताओं के कारण, उत्पादन, सार्वजनिक आय बढ़ाने में PSUs ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किंतु इनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ हैं -

- (i) लगातार घाटे में चलते रहना
- (ii) प्रति-इकाई उत्पादन में नियोजित शक्ति संरका अधिक।
- (iii) राजनीतिक हस्तक्षेप

(iv) मशीनीकरण का अभाव ।

इस चुनौतियों से निपटने के लिए PSU की एकीकृत बिक्री एक लाकड़ी कर हो सकता है, इसके निम्नांकित लाभ होंगे -

- (i) नवीन निवेश पूंजी आने से PSU की दक्षता बढ़ेगी तथा सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ता को बल मिलेगा।
- (ii) मिली फार्मों की भागीदारी 50% से ज्यादा होने से प्रबंधन की जिम्मेदारी से सरकार की मुक्ति मिलेगी अतः सरकारी मशीनरी का उपयोग अन्य वंचित क्षेत्रों में किया जा सकेगा।
- (iii) कॉर-सर्विसेस समाप्त होने से बेहतर उत्पादन करने वाले PSU की दक्षता बढ़ेगी।
- (iv) मिली निवेश बढ़ने से तकनीकी ऊन्नत, श्रम दक्षता, पूंजी प्रबंधन दक्षता में वृद्धि होगी अतः जीत इकट्ठी उत्पादन लागत कम होगी।

रणनीतिक बिक्री के लिए निम्नांकित
दुस्साव आवश्यक हैं -

- (i) रणनीतिक बिक्री के बाद वंचित क्षेत्रों
में निजी क्षेत्र को बजार रखने के लिए
विशेष हठों का पालन करना चाहिए।
- (ii) आर्थिक स्फूर्ति काल में कमजोर कंपनियों
की बिक्री ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी।
- (iii) पारदर्शितापूर्ण बिक्री प्रक्रिया को अपनाया
जाना चाहिए।

5. Shell companies in India are neither legally defined nor properly understood. Analyse in the light of recent developments, prevalent understanding and steps required to effectively deal with shell companies.

भारत में शेल कंपनियां न तो कानूनी रूप से परिभाषित हैं और न ही उनके विषय में उचित समझ है। हाल के घटनाक्रमों, व्याप्त (प्रचलित) समझ और शेल कंपनियों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आवश्यक कदमों के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

शेल कंपनियों के माध्यम से
वैकल्पिक निवेशक का अपवंचन करती हैं।
तथा संबंधित देशों की का लंघना से
बचते हुए अवांछित लाभ कमाती हैं।
इन कंपनियों के माध्यम से वैकल्पिक
भारतीय कंपनियां भी राउण्ड ट्रिपिंग की
सहायता लेती हैं तथा बायबैक करती हैं।
अतः देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान
होता है।

भारत में शेल कंपनियों के संबंध में
स्पष्ट परिभाषा का अभाव होने एवं
स्पष्ट नीतिगत/वैकल्पिक प्रावधानों का अभाव
होने के कारण ये कंपनियां आर्थिक
अस्थिरता का कारण बन सकती हैं।

हाल में भारतीय राशि से अत्यधिक निवेश, मोबाइल कल-अपवंचन मानक आदि के कारण बड़े आर्थिक हकान भार सरकार को झेलने पड़े हैं अतः और कंपनियों पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके निम्नांकित उपाय हो सकते हैं -

- (i) विभिन्न देशों के साथ डबल टैक्स अवार्डेंस एक्ट (DTAA) को संशोधित करना एवं कठोर रूप से अनुकूल भागी के साथ लागू करना।
- (ii) अमेरिका के 'FATCA' के माध्यम से वैश्विक वित्तीय सूचना साझाकरण करना एवं समुचित कार्यवाही करना।
- (iii) फॉरडोफॉर्म (मनी लॉसिंग) के खिलाफ FATF (Financial Action Task Force) का मजबूत क्रियावधन करना।
- (iv) बीसा के स्वीटपॉलेंस के साथ क्रिया गया है अन्य टैक्स हेवन देशों के

साथ की विपरीत करारों के माध्यम से
पूँचता (प्राप्ति) करण ।

वैश्विक सहयोग के साथ ही भारत
की विभिन्न वित्तीय आधुनिक मशीनरी
को आधुनिक एवं सज्जित करण होगा
ताकि किसी की पुकार की विवेक को
पकड़ा जा सके ।

6. If a larger population in India is to be involved in the economy in a big way, Small and Medium Enterprises (SMEs) are key. Elaborate. Also discuss the challenges faced by the SME sector in India and give an account of the measures taken by the government to deal with these.

यदि भारत में एक बड़ी आबादी को अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर सम्मिलित करना है, तो लघु और मध्यम उद्यम (SMEs) महत्वपूर्ण हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए। इसके साथ ही, भारत में SME क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिए और इनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी प्रदान कीजिए।

भारत में रोजगार सृजन, निर्यात बढ़ाने एवं ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्र की उन्नति के लिए SMEs का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। SMEs के माध्यम से साथ विनिर्माण, कृषि उत्पादों का नियोजन एवं ग्रामीण / स्थानीय बाजार की पूर्ति वहनीय कीमतों पर की जा सकरी है।

SME क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियां निम्नांकित हैं:-

- (i) अवसर-चलात्मक पिछड़ेपन के कारण, विद्युत आपूर्ति, बैंकिंग सुविधा, परिवहन सुविधा का अभाव होने से SMEs

हरेक की दूसरी इकाइयों का लोफ नही
उदाया जा सकता है।

(iii) तकनीकी उन्नयन एवं कौशलीकृत श्रम के
उपभाव में वैश्विक परिवर्तन में
पिछड़ना ,

(iii) ~~क~~ ज्यादातर SME उद्योग को
संरक्षण की श्रेणी में आला गया है
अतः जिली निवेश के उपभाव में यह
तकनीकी रूप से पिछड़ा एवं एक
असंगठित इकाय बन हुआ है।

(iv) विपणन सुविधा / विपणन तंत्र की वजह
के उपभाव में बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का
निर्माण हो जाता है अतः वास्तविक
लोफ उत्पादों तक नही पहुँच पाता है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम निम्नांकित हैं:

- (i) मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण प्रदान करना।
- (ii) स्टेप-अप इण्डिया के माध्यम से गरीब वर्गों की रक्षा में SC, ST, महिला उद्यमियों का सहयोग।
- (iii) कौशल भारत मिशन द्वारा कौशलविकास प्रदान करना।
- (iv) उत्पाद योजना द्वारा उपभोक्ताक उद्यमिता को बढ़ावा।
- (v) भारत बाव का विकास कर विपणन
- (vi) सरकारी खरीद में MSME ब्रांच के उत्पादों को प्राथमिकता।



7. What are the reasons for the growing informalization of industrial labour in India? Discuss the issues associated with the phenomenon and reforms required to deal with them.

भारत में औद्योगिक श्रम के बढ़ते अनौपचारिकरण के क्या कारण हैं? इस परिघटना से जुड़े मुद्दों और उनसे निपटने हेतु आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए।

भारत में औद्योगिक श्रम के बढ़ते
अनौपचारिकरण के ~~बढ़ते~~ विभिन्न कारण हैं -

- (i) संगठित क्षेत्र में जटिल श्रम कागूठ होने
के कारण उद्यमी अनौपचारिक क्षेत्र
में बने रहना चाहते हैं।
- (ii) औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक इकाइयों की
नगण्य भागीदारी के कारण औपचारिकरण
नहीं बढ़ पाता जबकि ~~उस~~ सार्वजनिक
इकाइयों औपचारिकरण को बढ़ावा देती
हैं।

अनौपचारिकरण के संदर्भ में मुख्य मुद्दे -

- (i) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षाएं प्राप्त नहीं
हो पाती हैं तथा उन्हें प्रतिकूल सेवाशर्तों के
भी कार्य करना पड़ता है।

(ii) अंकिता प्रयोग ~~ह~~ में दस्ता नहीं
आ पाती है अतः 'विक्रिण उद्देश्यो' का
वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त किया जा
सकता है।

(iii) अग्रोपचारिक स्तरों में कौशल विकास,
वोकेशनल प्रशिक्षण पर नागण्य भाव
में निवेश किया जाता है अतः नियोजित
श्रमिक कम-उत्पादक बने रहते हैं।

(iv) सरकार की कल-गति नकारात्मक
रूप में प्रभाव होती है।

निम्नलिखित हेतु गणाय →

(i) उदात्त श्रम मानक बनाकर तथा सभी
हितचार्कों की भागीदारी सुनिश्चित
कर श्रम कागूक निर्माण करना ताकि
उनका पालन आसान हो सके।

(ii) पारदर्शितापूर्ण कल-ढाँचे की व्यवस्था

करना ताकि कर-चोरी से बचन मुश्किल
हो तथा औपचारिकता बढ़ें। LAST
इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

8. A number of far-reaching developments have taken place in the local and global energy space which have to be reflected in our own energy policy framework. Discuss.

स्थानीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में कई दूरगामी घटनाएं घटित हुई हैं, जिन्हें हमारी अपनी ऊर्जा नीति के ढांचे में प्रतिबिंबित होना है। चर्चा कीजिए।

भारत शुद्ध ऊर्जा आयातक देश है तथा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 80% से अधिक अंश की प्रति ऊर्जा आयात से करता है। चूंकि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रगत हो चुकी है अतः वैश्विक स्तर की प्रत्येक घटना भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।

स्थानीय और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में घटित दूरगामी घटनाएं एवं उनके भारत पर प्रभाव निम्नलिखित हैं -

- (i) वैश्विक मंदी के कारण जीवाश्म ईंधन के मूल्यों में भारी कमी।
- (ii) तेल गैस एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के कारण परम्परागत ऊर्जा के मूल्य में भारी कटौती।

(iii) मुख्य तेल उत्पादकों में अपने भण्डारों के तीव्र दोहन का पश्चिकाधिक लाभ कम करने के लिए प्रतिस्पर्धी

(iv) पर्यावणीय सिंताएं उभरना।

इस घटनाओं के कारण भारत की ऊर्जा नीति पर निम्नांकित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं -

(i) वैश्विक ऊर्जा कीमतों के सतते होने से भारत ऊर्जा के 201 नीतिक भण्डार तैयार करने की ओर अग्रसर है।

(ii) नवीकरणीय स्रोतों की अपेक्षा पारम्परिक ऊर्जा की कीमते लगातार गिरने के कारण नवीकरणीय क्षेत्र में उगतिशीलता बढ़ सकती है तथा स्थानीय स्रोतों का दोहन महंगा साबित हो सकता है।

9. The Indian IT-BPM (Information Technology-Business Process Management) industry is a global powerhouse today and its impact on India and the world has been unprecedented. Comment. Also, mention the challenges being faced by India's IT-BPM sector.

भारतीय IT-BPM (Information Technology-Business Process Management या सूचना प्रौद्योगिकी-व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन) उद्योग आज एक वैश्विक शक्ति का केंद्र है और भारत एवं विश्व पर इसका प्रभाव अभूतपूर्व रहा है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, भारत के IT-BPM क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारत में IT-BPM के लिए अद्भुत परिस्थितियों के जिज्ञासित कारण हैं -

- (i) शिक्षित, पश्चात्त एवं अंग्रेजी भाषा में निपुण मानव शक्ति जो वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- (ii) निम्न एवं प्रतिस्पर्धी श्रममूल्य।
- (iii) स्वातंत्र्य बाजार की उपस्थिति।

IT-BPM उद्योग ने भारत में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन, भारतीय सॉफ्टवेयर का उभार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह उद्योग भारत में तीव्रतम संवृद्धि वाले उद्योगों में से एक रहा है।

IT-BPM का भारत पर प्रभाव -

- (i) भारतीय भुवाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव
- (ii) रोजगार (वृद्धि) एवं विदेशी मुद्रा अर्जन

विश्व पर प्रभाव -

- (i) बहुराष्ट्रीय कंपनियों की लागत कम होने के कारण उनका वैश्विक प्रसार बढ़ता है (वक)।
- (ii) प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होने से सेवा गुणवत्ता मजबूत हुई।

वर्तमान में IT-BPM उद्योग के प्रमुख चुनौतियाँ -

- (i) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं ऑटोमेशन।
- (ii) इण्डोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों द्वारा तीव्र प्रतिस्पर्धा
- (iii) बढ़ता ~~वक~~ वैश्विक संस्करणवाद।

उपरोक्त चुनौतियों से लड़ने के लिए
भारतीय IT उद्योग को समाधानकर्ता की
बजाय समस्या खोजकर्ता बन चुकिया -
बढ़ता बना होगा तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा
से आगे बढ़कर विश्वीकृत होंगे जैसे
चिबिता, पब्लिक चणाली तथा नवीन देशों
में जैसे अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका
में अपना उल्ला करना पड़ेगा।

10. An effective multi-modal logistics and transport sector will make the Indian economy more competitive. Analyse.

एक प्रभावी मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स (बहु-रूपात्मक संभरण) और परिवहन क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। विश्लेषण कीजिए।

किसी भी देश की परिवहन प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था की सीढ़ की तरह कार्य करती है। निवेश को आकर्षित करने, प्रादेशिक विषमता दूर करने, बाजार एकीकरण तथा सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला के निर्माण के लिए परिवहन प्रणाली की प्रगति-आवश्यक है।

सड़कमार्ग, रेलमार्ग, वायुमार्ग एवं अन्तर्जलीय जलमार्ग के एकीकरण से निर्मित परिवहन व्यवस्था को मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स के रूप में ~~संज्ञित~~ संज्ञित किया जा सकता है, जो कच्चे एवं निर्मित माल की तीव्र एवं बहनीय कीमतों पर पारिभाषिक पहुँच प्रतिबिम्बित करता है।

विकसित एवं उष्णोष्ण मल्ली - मॉडल लॉजिस्टिक्स
एवं परिवहन क्षेत्र के उपयोग के
निम्नांकित लाभ हो सकते हैं -

- (i) यह ईल ऑफ डूंग बिलनेल में उष्णोष्ण
लकारात्मक भूमिका निभाता है अतः वैश्विक
~~वैश्व~~ निवेश की प्रति को आकर्षित करता
है।
- (ii) प्रत्येक प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन क्षमता
का पूर्ण दायित्व संभालता है तथा
एक-लाभ का निर्माण कर वहनीय
कीमतों पर उपयोग वस्तुएं मुक्ति प्रदान
करता है, जिससे मांग बढ़ती है।
- (iii) देश का प्रत्येक प्रदेश एवं क्षेत्र का
वैश्विक व्यापार में उष्णोष्ण भूमिका निभाता
है।
- (iv) अवसंरचनात्मक विकास की दिशा में
सीमेंट, लौह, विनिर्माण उद्योग को प्रबलता
प्रदान होती है।

11. Climate change threatens sustainable development, impairs socio-economic development and reinforces cycles of poverty across the globe. In this context, discuss the utility of climate risk insurance as an instrument within a comprehensive climate risk management system.

जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में संधारणीय विकास को जोखिम में डालता है, सामाजिक-आर्थिक विकास को क्षीण करता है और गरीबी के चक्र को मजबूत बनाता है। इस संदर्भ में, व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एक साधन के रूप में जलवायु जोखिम बीमा की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।

स्थानीय मौसम उत्तिक्रम में स्थायी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की दलता के साथ सामाजिक दलता को भी गहरात्मक रूप से प्रभावित किया जाता है, जिसके निष्कांतित सामाजिक-आर्थिक परिणाम होते हैं-

- (i) चरम मौसमी घटनाओं के कारण आपक ज्ञान-माल की क्षति होती है तथा पुनर्निर्माण पर अत्यधिक खर्च से विकास प्रक्रिया कई वर्ष पीछे चली जाती है।
- (ii) तापमान तथा वर्षा के उत्तिक्रम में परिवर्तन आने से भूकृ-उत्पादकता कमजोर होती है तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में कृषि भूभाग की आवश्यकता होती

हैं। अतः कृषि-कार्य अलोककारी हो जाता है।

(iii) पशुओं एवं मनुष्य की दशा कम होने से अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

(iv) दीर्घ एवं तीव्र प्रदूषणों में जलमयंत्र के कारण कृषि भूमि का क्षय होता है।

उपरोक्त कारणों से जलवायु-शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा भूमि-परिवर्तन के कारण शोध भूमि पर दबाव अत्यधिक होने से उनकी दशा कम हो जाती है।

जलवायु जोखिम रीमा चरम जलवायवी परिवर्तनों के प्रति समुदायों की सुशिक्षण की जरूरत है तथा लोगों में नवीनमेष अपनाने की शक्ति को

बढ़ाता है। जल-चक्रण से लोग नदी
उत्पन्न अवधारणाओं जैसे जल-जल,
शुष्क क्षेत्रों के प्रति सकारात्मक
अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं।

12. Why are women particularly vulnerable to the impact of natural disasters? Also analyse, with adequate examples, how women can play a more effective role in disaster risk management cycle.

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों के प्रति महिलाएं विशेष रूप से सुभेद्य क्यों होती हैं? साथ ही, समुचित उदाहरणों के साथ विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार महिलाएं आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

प्राकृतिक संकट जब आपक स्तर पर मान-माल की क्षति करता है तब वह प्राकृतिक आपदा कहलाता है। प्राकृतिक संकट जब किसी ~~सांस्कृतिक~~ सुभेद्यता से गुणित होता है तब प्राकृतिक आपदा की तीव्रता की गणना होती है।

$$\text{आपदा की तीव्रता} = \frac{\text{संकट की तीव्रता} \times \text{सुभेद्यता}}{\text{तीव्रता}}$$

यह कारण है कि विकसित एवं औद्योगिक देशों में सामान्य संकट की गंभीर आपदा का स्वरूप कारण बन जाता है।

~~यदि~~ महिलाओं की सुभेद्यता अधिक

होने के निम्नांकित कारण हैं -

- (i) महिला की पेंसिक सीमितताएं, जैसे गर्भविज्ञा आदि उनकी मतिशीलता सीमित करती हैं।
- (ii) पितृसत्तात्मक समाज में सम्पूर्ण जिम्मेदारी महिला पर डाल दी जाती है अतः वह शारीरिक रूप से कमजोर सामने होती है तथा आपदा के प्रति लुब्ध हो जाती है।
- (iii) आपदा के समय सभी सदस्यों के जाने के बाद भोजन करना तथा गरीब घरों में सीमित ~~सामान~~ साधन-पदार्थों के कारण सामान्यतः महिलाएं झुंझी रहकर 'आने वाले दिनों' से परिवार के भरण-पोषण की चिंता करने लगती हैं अतः वे शारीरिक कमजोरी से ग्रसित हो जाती हैं।
- (iv) लंचाव करने वाली मशीनरी तक पहुँचने में भी लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं।

औद्योगिक प्रबंधन में महिलाएं अधिक
उत्पत्तिकाशी सिद्ध हो सकी हैं क्योंकि -

- (i) सामान्यतः महिलाओं में उच्च भावनात्मक-
वृद्धिमत्ता गुणांक (EQ) होता है अतः वे
सामूहिक प्रयासों एवं आपसी समन्वय
में अधिक कारगर सिद्ध होती हैं।
- (ii) खाद्य-पदार्थों का निर्यात - प्रबंधन में
महिलाएं अधिक फल होती हैं।
- (iii) ककला एवं दया तत्त्व समाजशास्त्र की
भावना महिलाओं में सामान्यतः अधिक
होती है अतः वंचित समूहों जैसे
बुढ़ों, दिव्यांग लोगों, स्त्री, वरुणों, मरीजों
के कल्याण में महिलाएं अधिक
प्रयास करेंगी।

13. In view of the seriousness of heat waves and its consequences, greater attention is required for dealing with it as a natural disaster. Analyse in the context of recent developments and the actions taken by relevant government bodies.

हीट वेव (ग्रीष्म लहर) और उसके परिणामों की गंभीरता के आलोक में, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इससे निपटने हेतु अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हाल के घटनाक्रमों और संबद्ध सरकारी निकायों द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थानीय तापमान में अचानक से $5-6^{\circ}\text{C}$ तापमान वृद्धि होना या तापमान का 45°C से उपर होना, 'हीट वेव' के रूप में गणना किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसम दशाओं के कारण हीट वेव का प्रभाव समय, प्रसार क्षेत्र, ~~कठोर~~ तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है। इसके निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं -

- (i) स्थानीय जलनिकास तैली से शुष्क हो जाते हैं।
- (ii) जल की कमी से जलित रोग होने लगते हैं, जो वृद्धों को अधिक प्रभावित

करते हैं।

(iii) वृद्धजनों की मॉलपेसिंगो में अत्यधिक
खिंचाव उत्पन्न होने से उनकी मृत्यु
तक हो जाती है।

(iv) पशु-पक्षी अत्यधिक उत्साहित होते हैं क्योंकि
हरी घास जल जाती है तथा उनके
लिए जल उपलब्धता समाप्त हो जाती
है।

हीट वेव की तीव्र होती समस्या से
बिपत्तों के लिए सारकारी उपाय -

(i) भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा
समय से पूर्व हीट वेव की घोषणा
की जाती जाये लगी है।

(ii) वृद्धाश्रमों को बढ़ावा देकर हीट वेव
के प्रभावों से बिपत्तों के प्रयास

(iii) सारकारी उद्घाटन द्वारा संबंधित चिकित्सा
सेवाएं एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित
करना।

हीट वेव की तीव्र होती समस्या है
मिटाने के लिए आपको हर पद परकारी
उपायों के साथ ही जन-जागीरों को
दुर्गिच्छित करने की आवश्यकता है। इसके
द्वारा निम्नलिखित उपायों को बल मिल सकता
है -

- (i) वृक्ष कटाई को रोकना।
- (ii) वर्षा जल का अत्यधिक संग्रहण।
- (iii) प्राकृतिक जल-विकासों का संरक्षण।

14. While genome editing offers immense potential benefits in the area of healthcare, there are a lot of apprehensions regarding its use. Discuss.

जहां, जीनोम एडिटिंग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ की संभावना प्रस्तुत करता है, वहीं इसके उपयोग के संबंध में काफी आशंकाएं भी मौजूद हैं। चर्चा कीजिए।

जीनोम एडिटिंग एक आनुवंशिक तकनीक है, जो आणविक स्तर पर कार्य करती है। जीनोम एडिटिंग में किसी जीनोम में परिवर्तन करने के लिए लक्षित ~~कोई~~ जीन या जीन खण्ड को काटकर हटाना, प्रतिस्थापित करना एवं वांछित ~~कोई~~ गुणों वाले जीन का जीनोम में एकीकरण करना शामिल किया जाता है।

जीनोम एडिटिंग तकनीक की सफलता की दर बढ़ाने के लिए CRISPR/Cas-9 तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो लक्षित खण्ड को ही एडिट करती है।

अक्सर की कुछ लक्षणात्मक आनुवंशिक बीमारियों के उपचार में यह तकनीक अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है। यही कारण है कि यह तकनीकी क्षेत्र में

CRISPR/Cas-9 तकनीक को ~~दुनिया~~ दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है।

इसके विभाजित भाग हैं:-

- (i) आनुवांशिक बीमारियों / कृमियों को एक बार उपचारित कर सम्पूर्ण पीढ़ियों से हटाया जा सकता है।
- (ii) कैंसर, मैलेरिया आदि जैसी जटिल बीमारियों के ~~लिए~~ उपचार के लिए आवश्यक रसायन का निर्माण शरीर के अन्दर ही वांछित गुणों वाले जीन का प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को ~~जैव~~ जीन ड्राइव या आनुवांशिक टीका कहते हैं।
- (iii) कुछ कीटों में आनुवांशिक बदलाव कर उनके लार्वा को बढ़ाया जा सकता है तब उनकी नकारात्मकताओं को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मलेरिया मच्छर की विधायुवाहक क्षमता को नष्ट करना।
- (iv) फसलों में / पशुओं में आनुवांशिक बदलाव कर उनकी उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है।

जीन एडिटिंग तकनीक के समस्त सिद्धांत -

- (i) यह तकनीक डिजायन वेबी की संकल्पना पर चल देती है, जो कि भविष्य में सिर्फ चर्ची लोगों का दृष्टिकोण बनकर रह सकती है और एक नवीन सामाजिक शिक्षालय को उत्पन्न कर सकती है।
- (ii) जीनोम में कृत्रिम परिवर्तन कुछ भावी उद्घाटन उत्परिवर्तनों को पैदा कर सकता है, जिसका उद्घाटन आने वाली सभी जीवियों में भी हो सकता है।

जीन एडिटिंग तकनीक एक तटस्थ विज्ञान है अतः इसका उपयोग मानवता के विकास के लिए होना चाहिए। ~~यह~~ इस तकनीक को एक प्रसुम्बित (facilitating) के रूप में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए।

15. Discuss various ways in which supercomputers have benefitted mankind over the years. Also enumerate the objectives of the National Supercomputing Mission and the mechanism for its implementation.

उन विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए जिसके माध्यम से विगत वर्षों में सुपर कंप्यूटरों ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन के तंत्र को भी सूचीबद्ध कीजिए।

सुपर कम्प्यूटर समानांतर प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित एक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तकनीक है, जो एक लाख अथवा अधिक पारलल गणनाओं को प्रत्यक्ष समय में संपादित कर सकती है। सुपर-कम्प्यूटर ने विभिन्न तरीकों से जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है -

- (i) विभिन्न मौसमी दशाओं से संबंधित आंकड़ों के प्रसंस्करण द्वारा दीर्घकाल तक मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु-परिवर्तन पैटर्न का पता लगाया जा सकता है।
- (ii) कस्म दवाओं का निर्माण संभव हो सकता है। अतः सुपरकम्प्यूटर के माध्यम से अस्तिगत स्तर पर आणविक संरचना के अणुगत दवाओं का निर्माण संभव है, जो

आर्थिक दृष्टापूर्व इलाज करने में सक्षम हैं।

(iii) सुपरकम्प्यूटर द्वारा सैंकड़ों वर्षों में परिणाम देने वाले एक्सपेरिमेंट कुछ घंटों में संपादित कर लिए जाते हैं।

• उदाहरण के लिए परमाणु हथियारों की प्रभावोत्पादकता की गणना ~~बिना~~ वास्तविक परीक्षण के तय की जा सकती है।

(iv) आर्टिफिशियल दवाइयों का निर्माण कर ~~बायोलॉजिक~~ वायुयानों के पायलटों, समुद्री (वहमरीन में जाने वाले लोगों को तैयार किया जा सकता है।

• राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटर मिशन के उद्देश्य -

→ विकिज्ज देशों से संबंधित देशभर में 100 सुपरकम्प्यूटर्स का निर्माण करना।

- ~~हैं~~ एक्सप्लॉस तक की गति के सुपरकम्प्यूटर्स का निर्माण कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को चुनौती देना।
- मिड का निर्माण कर सभी विश्व-विश्वको एवं अंतराष्ट्रीय केन्द्रों को भी सुपरकम्प्यूटर्स का लाभ उठान करना।

भारत में सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कम्प्यूटिंग (C-DAC) नामक संस्था है। इसकी पहलुओं से विभिन्न IITs, IISc में सुपरकम्प्यूटर्स की स्थापना की जा रही है।

16. Widely seen as a disruption for the traditional banking and financial institutions, cryptocurrencies have gained significant traction lately, at the same time creating a regulatory nightmare for regulators across the globe. Discuss.

पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के लिए व्यापक रूप से व्यवधान के रूप में देखी जाने वाली, साथ ही विश्व भर में नियामकों के लिए एक नियामकीय दुःस्वप्न का निर्माण करने वाली, क्रिप्टोकॉइन्स ने हाल ही में महत्वपूर्ण पकड़ स्थापित की है। चर्चा कीजिए।

वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकार के मुद्रा स्वरूपों यथा, स्वर्णमुद्रा, कागजी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा पर किसी ना किसी प्रकार की विनियामक संस्था का नियंत्रण शासित है। क्रिप्टोकॉइन्स ने इसे किसी की विनियामक संस्था के मुक्त करेला है।

क्रिप्टोकॉइन्स के निम्नांकित गुण इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं -

(i) इस क्रॉइन्स का सृजन ब्लॉक चेन तकनीक से होती है अतः यह अत्यधिक सुरक्षित, जागी मुद्रा से मुक्त एवं क्रॉइन्स में मैनुपुलेशन से मुक्त है।

(ii) इस क्रॉइन्स का अंतरण किसी व्यक्तिगत

पैसे पर नहीं होकर एक विशेष पैसे पर होता है, जो व्यक्तिगत पहचान से मुक्त होता है। इस प्रक्रिया से करेंसी अंतरण किस व्यक्ति से किसके पास हो रहा है यह पहचानना मुश्किल है किन्तु यह बात सभी हितधारकों को पता चल जाती है कि ~~कौन~~ करेंसी अंतरण किस दिशा में हो रहा है। अतः कालाबाजारी नहीं हो सकती है।

(iii) क्रिप्टोकॉइन्स में उपयोग होने वाली तकनीक विकिज्ज वेंडिंग प्रणालियों में करत से किसी भी प्रकार के वेंडिंग फ्राड की संभावना नगण्य हो जाती है।

(iv) सीमित संख्या में करेंसी होगा एवं करेंसी का गैर-वित्तियत प्रयोजन होगा अवैध या अवैध प्रयोजन की संभावनाओं को नगण्य करत है।

हालांकि कितने करेंगी कुछ चिंताओं का भी ध्यान करती है जैसे -

- ↳ आतंकवाद एवं संगठित अपराधों का निःशोषण ।
- ↳ किली भी प्रकार का विनिष्पन्न नहीं होने से सम्पूर्ण तंत्र के असफल होने की दशा में अबाधदेहिता का अभाव ।

गिरिजा तोर पर कितने करेंगी एक सुरक्षित एवं पारदर्शी अंतरण का ध्यान कर लेकता है । किन्तु इस पर सीमित मात्रा में समन्वयपूर्ण क्रियम आवश्यक है ।

—————

17. An internationally-binding agreement to strengthen the Outer Space Treaty of 1967 is both desirable and increasingly a necessity. Analyse in view of the traditional and emerging challenges in this arena.

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि को मजबूत बनाने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता वांछनीय और साथ ही एक आवश्यकता दोनों है। इस क्षेत्र में पारंपरिक और उभरती हुई चुनौतियों के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

अंतर्राष्ट्रीय दूरगंचाल संधि (ITU)
कारा घालायेत 1967 की बाह्य ~~अंतरिक्ष~~ अंतरिक्ष
संधि ~~संधि~~ अंतरिक्ष को कॉमन गुड घोषित
करती है जिसमें निम्नांकित प्रावधान हैं -

(i) समुद्रतल से 100 किलोमीटर ऊपर कार्मैन
रेखा से उपर अंतरिक्ष ऐज पर किसी
भी देश का अधिकार नहीं है।

(ii) अंतरिक्ष का दोहन मानवता के लिए होगा
तथा अंतरिक्ष यान तथा मानव प्रस्थी के
प्रतिनिधि होंगे किन्तु इनकी ~~होती~~
होती संबंधित देश को ही उबानी पड़ेगी

(iii) अंतरिक्ष कक्षाओं में परमाणु हथियार स्थापित
नहीं किए जा सकते। अंतरिक्ष का उपयोग
शान्तिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।

गैर अंतरिक्ष संघ के बावजूद कुछ नवीन समस्याएं उभर चुकी हैं, जिनका समाधान आवश्यक है - जैसे -

- (i) अंतरिक्ष कक्षाएं एक सीमित संसाधन हैं। अतः अंतरिक्ष तकनीकी से सम्बन्धित राष्ट्रों ने अंतरिक्ष में ओवर क्राउडिंग को अंतरिक्ष सेवाओं का व्यावसायीकरण को दिया है। इसके फलस्वरूप नये राष्ट्रों को सीमित अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अंतरिक्ष उपनिवेशवाद की स्थिति से बचने के लिए सभी राष्ट्रों का कोटा निर्धारित करना चाहिए। कोटा से अधिक उपयोग पर उसे अपनी सेवाएं वंशित राष्ट्रों को बियसरी कोष पर देना चाहिए।

- (ii) अंतरिक्ष उद्घरण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उपग्रह छींके बरत देना ही कार्यकाल समाप्त पर उस

कचरे का निपटारा करे या करवाये।
असंवैधानशील कदमों से बचने के लिए
स्पष्ट नियम आवश्यक हैं। उदाहरण के
लिए चीन द्वारा प्रायोगिक परीक्षण के लिए
अपने ही उपग्रह को लॉन्च कर तोड़ा गया
जिससे भारी मात्रा में अंतरिक्ष कचरा
पैदा हुआ। अतः इन कदमों पर पुष्कळी
अवावहेदिए। लुकिछिपी करना चाहिए।

18. Even after nearly 60 years in existence, AFSPA remains at the centre of debates with respect to countering violent insurgencies, role of the states and local communities. Discuss.

अस्तित्व में आने के लगभग 60 वर्षों के बाद भी, हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने और राज्यों व स्थानीय समुदायों की भूमिका को लेकर AFSPA वाद-विवाद के केंद्र में बना हुआ है। चर्चा कीजिए।

AFSPA

→ हलाने के पक्ष में तर्क

- मानवाधिकारों का हलन
- सुरक्षा बलों के कुछ सदस्य अमानवीय तरीके से बर्ताव करते हैं।
- विभिन्न उग्रवादी समूह AFSPA का लक्ष्य लेकर आम लोगों में सापेक्षिक बेचैन की भावना का प्रसार करते हैं और सामान्यजन को डकलते हैं।

→ लगे रहने के पक्ष में तर्क

- विभिन्न प्रकार के देश-विदेशी ताकतों का प्रभाव समाप्त करना तथा हलन, अराजकता (अस्थिरता) को दूर करना।
- अशांत क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना।

सुझाव -

→ स्थानीय पुलिस को मजबूत बनाना

उदाहरण - सिपुटा

→ कमबख्त तरीके से AFSPA को हटाकर
जनसमूह को शांति बहाल करने के लिए
उत्तेजित करना।

→ वैदेशी प्रभावों को कम करने के लिए
उनके प्रभाव को नगण्य करना।

19. Analyse the challenges and opportunities inherent in the push for indigenisation of defence production in India. Also, identify the measures through which indigenous manufacturing of defence equipments is being encouraged by the Government.

भारत में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण की दिशा में निहित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, उन उपायों की भी पहचान कीजिए जिनके माध्यम से रक्षा उपकरणों का स्वदेशी निर्माण सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

20. India's ability to pursue a clear-cut strategic vision depends on its ability to improve institutional cooperation and coordination between the armed forces and civilian bureaucracy. Discuss.

भारत द्वारा एक सुस्पष्ट रणनीतिक दृष्टि का अनुसरण करने की क्षमता वस्तुतः सशस्त्र बलों और सिविल नौकरशाही के बीच संस्थागत सहयोग और समन्वय में सुधार करने की क्षमता पर निर्भर करती है। चर्चा कीजिए।

